



संपादकीय

क्या हाथ खींच रही है सरकार

आम तौर पर किसानों के गेहूँ में टूटे या गोले दानों की मात्रा 6 फीसदी तक होने पर ही उसकी खरीद सरकारी केंद्रीय पर होती थी। इस बार वह सीमा सीधे 18 फीसदी कर दी गई है जबकि गेहूँ की कटनी के समय फसल के अन्धेरे और बर्बाद होने की खबर बहुत कम है। बल्कि इस बार फसल रहते हुए भारत सेंज काफी फसल गिर गई थी तब बाबां का अदिशा जाता या जा रहा था।

पहली जून को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के रिलायंस में जब सरकार की तरफ से 30 मई तक गेहूँ की 2.62 करोड़ टन अर्थात् पिछले साल के 1.88 करोड़ टन से काफी अधिक खरीद की सूचना दी गई हो तो सामान्य अधिक खरीदों ने भी इस खबर को प्रस्तुत की थी। टीवी रिलायंस में वह सूचना भी थी कि आदान-प्रदान काम करने वाले देखते खाते में 47000 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं।

निश्चित रूप से वे दोनों सूचनाएँ महत्वपूर्ण हैं और इनको प्रमुख जमान मिलनी चाहिए थी। पर किसी भी अधिकारी ने वह सबकठन की कोंशिंग नहीं की कि अब गेहूँ उत्पादन और खरीद को स्थित इनी अच्छी तरह गेहूँ की खुली गांजी की कमीते हांस लगायी ही है। फिर वह महीने में गेहूँ की कमीते हांस लगायी ही है, चढ़ाने नहीं। फिर वह समझने का प्रयास भी नहीं किया गया कि इसी समय चावल की कीमतों में तेजी क्यों दिखने लगी है जबकि पिछले साल फसल अच्छी हुई है और सरकार भी टूटे चावलों समेत लगाम हर किस्म के चावल के नियात पर सख्ती जारी रखे हुई हैं। साल भर में चावल के दाम औसत आठ फीसदी बढ़े हैं।

और धौर्यां रखें। इस आलेख का मतलब खाड़ान्न संकेत क्या महंगाई के एक और तैर की सूचना देकर आपको आर्तक करना नहीं है। ऐसा हुआ तो सरकार बख्शन वाली नहीं है। उसने गेहूँ के नियात में भी अधी कोई ठीक नहीं है जबकि यूक्रेन संकेत के बाद पहली बार खुले बाजार में हमारे गेहूँ की कीमतें नियात लावक बन गई थीं। सरकार की मुस्तैदी में महंगाई की चिंता या आम उपभोक्ता की चिंता न होने वह कहना मुश्किल है लेकिन ज्यादा तरह ज्यादा चिंतित है। इसलिए, जैसे ही कीमतों में ऊपर-नीचे होती है वह सख्त हो जाती है। संभव है खाद्य तेजों में वैश्विक गिरावट के बाद अपने वहां भी कीमतें कम हों। दलदार में फर्क पड़ा है। हालांकि मामला सिर्फ चन दाल का ही है। अहर और उड़द अभी भी परेशान का कारण है। दूसरी ओर वह ऐसे अंकड़े खास तौर से प्रचारित करती हैं जो अर्थव्यवस्था और खास तौर से खेतों की तस्वीर बहुत मुश्तरी बताते हैं। पिछले साल की गड़बड़ मासानु और फिर बिन बासान सेंज बासान से खरीद होने के चलते अन उत्पादन, खासकर गेहूँ के उत्पादन में गिरावट आई लैकिन जब सरकार ने दस तिमाही अंकड़ों में खेतों में 4.6 फीसदी के विकास का दावा किया तो काफी लोगों की भूंह तीनी थी।

इस बार भी गेहूँ के उत्पादन और खरीद को लेकर जिस तरह से अंकड़े दिए गए हैं उस पर भी उंगली उठ रही है। अम तौर पर किसानों के गेहूँ में टूटे या गोले दानों की मात्रा 6 फीसदी कर होने पर ही उसकी खरीद सरकारी केंद्रों पर होती थी। इस बार वह सीमा सीधे 18 फीसदी कर दी गई है जबकि गेहूँ की कटनी के समय फसल के भींगने और बर्बाद होने की खबर बहुत कम है।

बल्कि इस बार फसल रहते हुई बरसात से जब काफी फसल गिर गई थी तब बाबां के बाद फसल के बाद अपने वहां भी अधिकारी कीमतों नियात लावक बन गई थीं। सरकार की मुस्तैदी में महंगाई की चिंता या आम उपभोक्ता की चिंता न होने वह कहना मुश्किल है लेकिन ज्यादा तरह ज्यादा चिंतित है। इसलिए, जैसे ही कीमतों में ऊपर-नीचे होती है वह सख्त हो जाती है। संभव है खाद्य तेजों में वैश्विक गिरावट के बाद अपने वहां भी कीमतें कम हों। दलदार में फर्क पड़ा है। हालांकि मामला सिर्फ चन दाल का ही है। अहर और उड़द अभी भी परेशान का कारण है। दूसरी ओर वह ऐसे अंकड़े खास तौर से प्रचारित करती हैं जो अर्थव्यवस्था और खास तौर से खेतों की तस्वीर बहुत मुश्तरी बताते हैं। पिछले साल की गड़बड़ मासानु और फिर बिन बासान सेंज बासान से खरीद होने के चलते अन उत्पादन, खासकर गेहूँ के उत्पादन में गिरावट आई लैकिन जब सरकार ने दस तिमाही अंकड़ों में खेतों में 4.6 फीसदी के विकास का दावा किया तो काफी लोगों की भूंह तीनी थी।

मगर बेहोश कर दिए जाने के बाद ही। अब केरल से तमिलनाडू सीमावर्ती कुबुम घाटी के पास कलक्कन्ता गार्डीन बाब्य संरक्षण क्षेत्र में वह रखा गया है। अरिकंपन एक जगती हाथी है जिसकी दोनों तटबंधी दाक्षिणी राज्यों, केरल तथा तमिलनाडू की सरकारों (मार्क्कावादी और द्रविड़ मुनेन्त्र कजगम) गत कई सप्ताहों से पीछा कर रही है। वह गोराक नियात के बाद तमिलनाडू पुलिस ने जगतों में घेरकर भून दिया था। एक रणनीतिक नेट पर, नेपाल के साथ भारत के लोगों से

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा लाई संबंधों में और नजदीकी

- अरुण कुमार श्रीवास्तव

अन्य देशों में दौरा करने के लिए सबसे पहले भारत को चुनकर, नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पूर्ववर्तीयों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को भारत के साथ संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। इससे पता चलता है कि वह लोक लुभावनवाद पर व्यावहारिकता को चुन रहे हैं। नेपाल की संसद के लगभग अधिक सदस्य, जो विभिन्न काम्यूनिस्ट पार्टीयों से आते हैं।

इसे देखते हुए, भारतीय और नेपाली प्रतिनिधि मंडलों ने अपनामों के लिए शायद ही कोई गुंजाई थी और वेपासी जीवों की चिंता दिख रही है। जलविद्युत के साथ औपचारिक जुड़ाव पूरा किया और रुचि के स्थानों का दौरा किया। भारत के साथ नेपाल के पारंपरिक संबंधों से जुड़े महत्व को देखते हुए, दहल की भारत यात्रा को व्यावहारिकता के देखते हुए, और दोनों पक्षों के राजनीतिक नेता इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं।

नेपाली देखते हुए, भारतीय और नेपाली प्रतिनिधि मंडलों ने अपनामों के लिए शायद ही कोई गुंजाई थी और वेपासी जीवों की चिंता दिख रही है। जलविद्युत के साथ औपचारिक जुड़ाव पूरा किया और रुचि के स्थानों का दौरा किया। इससे पता चलता है कि वह लोक लुभावनवाद पर व्यावहारिकता को चुन रहे हैं।

अन्य देशों में दौरा करने के लिए सबसे पहले भारतीय योजना को अपनाने के बाद एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गयी है, जिसमें भारतीय सेना में गोरखा भर्ती शामिल नहीं है। भारतीय सेना में हृषि गोरखा बटालियन है, और उनके पास कुल गिरावट लगभग 40,000 सैनिक हैं। इनमें से कीरबी 12,000 नेपाली महल के गोरखा हैं। इसके अलावा, नेपाल में लगभग 120,000 गोरखा भारतीय सेना पेंशन-शोगी हैं। अर्थनयन पर हफल हर साल कीरबी 1000 गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता था। हालांकि, नेपाल के लगभग 600 गोरखा भर्ती शामिल नहीं हैं। नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में बुनियादी ढांचे और अन्य संबंधित पारंपरिक विविधताएँ जारी रखी गयी हैं। ज्यादा तरह ज्यादा चिंतित है।

जहां एक और भारत के भू-राजनीतिक और सामरिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि देखते हुए, नेपाल के साथ अपने वेपासी जीवों की चिंता दिख रही है। उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को भारत के साथ संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। इससे पता चलता है कि वह लोक लुभावनवाद पर व्यावहारिकता को चुन रहे हैं।

नेपाल की संसद के लगभग अधिक सदस्य, जो विभिन्न काम्यूनिस्ट पार्टीयों से आते हैं,



नेपाली देखते हुए, भारतीय और नेपाली प्रतिनिधि मंडलों ने अपनामों के लिए शायद ही कोई गुंजाई थी और वेपासी जीवों की चिंता दिख रही है। जलविद्युत के साथ औपचारिक जुड़ाव पूरा किया और रुचि के स्थानों का दौरा किया। भारत के साथ नेपाल के पारंपरिक संबंधों से जुड़े महत्व को देखते हुए, दहल की भारत यात्रा को व्यावहारिकता के देखते हुए, और दोनों पक्षों के राजनीतिक नेता इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं।

इसे देखते हुए, भारतीय और नेपाली प्रतिनिधि मंडलों ने अपनामों के लिए शायद ही कोई गुंजाई थी और वेपासी जीवों की चिंता दिख रही है। जलविद्युत के साथ औपचारिक जुड़ाव पूरा किया और रुचि के स्थानों का दौरा किया। इससे पता चलता है कि वह लोक लुभावनवाद पर व्यावहारिकता को चुन रहे हैं।

अन्य देशों में दौरा करने के लिए सबसे पहले भारतीय योजना को अपनाने के बाद एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गयी है, जिसमें भारतीय सेना में गोरखा भर्ती शामिल नहीं है। भारतीय सेना में हृषि गोरखा बटालियन है, और उनके पास कुर्बानी कीरबी 12,000 नेपाली महल के गोरखा हैं। इसके अलावा, नेपाल में लगभग 120,000 गोरखा भारतीय सेना पेंशन-शोगी हैं। अर्थनयन पर हफल हर साल कीरबी 1000 गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता था। इसके अलावा, नेपाल में लगभग 600 गोरखा भर्ती शामिल नहीं हैं। नेपाल ने भारत को विजयी बायांओं का बहावा देते हुए रोका था।

जलविद्युत नियात के म

